CBAM: कार्बन जवाबदेही, व्यापारिक तनाव और भारत की तैयारी

समाचार संदर्भ: 8 अक्टूबर 2026 की अमेरिकी सूचना | बाद का संदर्भ: 12 अक्टूबर का भारत–EU संवाद | GS-II व III

कार्बन की कीमत अब घरेलू पर्यावरण नीति तक सीमित नहीं है। निर्यात की प्रतिस्पर्धा में उत्पाद बनाने के दौरान हुए उत्सर्जन के विश्वसनीय आँकड़े भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं।

खबरों में क्यों

8 अक्टूबर 2026 की अमेरिकी आधिकारिक सूचना में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र और उसके प्रस्तावित विस्तार के व्यापारिक प्रभावों पर टिप्पणियाँ माँगी गईं। अंतिम तिथि 9 नवंबर 2026 है। यह सूचना अपने-आप प्रतिशोधी शुल्क लगाने या CBAM समाप्त करने का फैसला नहीं है। बाद में 12 अक्टूबर को भारत और EU ने कार्बन मूल्य, उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन पर तकनीकी संवाद जारी रखने पर सहमति जताई।

CBAM और कार्बन लीकेज

CBAM कुछ आयातित वस्तुओं के उत्पादन में निहित उत्सर्जन को कार्बन कीमत से जोड़ता है। इसका घोषित उद्देश्य कार्बन लीकेज रोकना है: कड़े पर्यावरण नियमों वाले क्षेत्र से उत्पादन का कमजोर नियमों वाले क्षेत्र में खिसकना, या अधिक उत्सर्जन वाले आयात से घरेलू उत्पाद का प्रतिस्थापन होना।

मुख्य तथ्य

दायरा और जिम्मेदारी: वर्तमान तंत्र चयनित लौह-इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन वस्तुओं से जुड़ा है। औपचारिक दायित्व EU आयातक अथवा संबंधित प्रतिनिधि पर होता है, लेकिन उसे विदेशी उत्पादक से उत्सर्जन की जानकारी चाहिए।

उत्सर्जन और कार्बन मूल्य: प्रमाणपत्रों की कीमत EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली से जुड़ी है। उत्पादन के दौरान पहले चुकाए गए कार्बन मूल्य को प्रमाणित करने पर संबंधित कटौती हो सकती है। केवल घरेलू कार्बन बाजार की घोषणा से कटौती स्वतः नहीं मिलती।

लागू व्यवस्था बनाम विस्तार: निश्चित व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू है। अमेरिकी सूचना के अनुसार इस्पात और एल्युमिनियम से आगे बनने वाली अतिरिक्त वस्तुओं तक विस्तार अभी यूरोपीय विधायी प्रक्रिया में है। प्रस्ताव को अंतिम कानून या सभी वस्तुओं पर लागू कर नहीं मानना चाहिए।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

भारत के सामने अवसर और कठिनाइयाँ

आँकड़ों की गुणवत्ता: उत्पाद-स्तर पर ऊर्जा और उत्सर्जन के विश्वसनीय रिकॉर्ड न हों तो सत्यापन महँगा हो सकता है और मानक उत्सर्जन-मूल्यों पर निर्भरता बढ़ सकती है। छोटे उद्यमों को साझा तकनीकी सहायता चाहिए।

हरित उत्पादन: कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा, संसाधन-दक्षता और पुनर्चक्रण से दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सकती है। किसी उत्पादन-तकनीक को उसकी बिजली और ईंधन के स्रोत देखे बिना शून्य-उत्सर्जन नहीं कहा जा सकता।

संवाद की सीमा: 12 अक्टूबर का भारत–EU संवाद मान्यता, पद्धतियों और क्षमता-विकास पर आगे काम करने का आधार है। इसे भारतीय सत्यापनकर्ताओं की पूर्ण मान्यता, कार्बन मूल्य की स्वचालित स्वीकृति या सामान्य छूट घोषित होना नहीं समझना चाहिए।

विश्लेषण और आगे की राह

भारत को उत्सर्जन मापन, रिपोर्टिंग और स्वतंत्र सत्यापन की भरोसेमंद क्षमता बढ़ानी चाहिए। निर्यातकों के लिए उत्पाद-स्तरीय डेटा व्यवस्था, छोटे उद्यमों की सहायता और साफ ऊर्जा तक पहुँच साथ-साथ विकसित हों। व्यापारिक संवाद में पारदर्शिता, समान व्यवहार और विकासशील देशों की क्षमता की बात उठे। अमेरिकी दबाव से भविष्य में राहत मिलेगी ही, इस अनुमान पर निवेश रोकना जोखिमपूर्ण है। घरेलू तैयारी का लक्ष्य केवल सीमा-लागत घटाना नहीं, बल्कि अधिक दक्ष और कम उत्सर्जन वाला उद्योग बनाना होना चाहिए।

अवधारणा में अंतर

मुक्त व्यापार समझौते में सामान्य आयात शुल्क घटाना और उत्पाद के निहित उत्सर्जन पर दायित्व अलग मुद्दे हैं। टिप्पणी माँगने की प्रक्रिया, व्यापारिक दंड और किसी देश को मिली अंतिम कानूनी छूट भी अलग हैं।

मेंस दृष्टि

GS-III में जलवायु नीति, उद्योग और निर्यात; GS-II में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। पर्यावरणीय उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए सत्यापन की लागत, समानता और विकासशील देशों की तकनीकी क्षमता को उत्तर में जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पर्यावरण नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार जोड़ता है? भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: CBAM चयनित आयातों के उत्पादन में निहित उत्सर्जन को कार्बन कीमत से जोड़ता है। उसका घोषित उद्देश्य कार्बन लीकेज रोकना है; इससे पर्यावरण नीति का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत और प्रतिस्पर्धा तक जाता है।

मुख्य भाग में: EU आयातक की औपचारिक जिम्मेदारी के लिए विदेशी उत्पादक का विश्वसनीय डेटा चाहिए। उत्पाद-स्तरीय रिकॉर्ड व सत्यापन की लागत छोटे उद्यमों के लिए कठिन हो सकती है। पहले चुकाए कार्बन मूल्य की प्रमाणित कटौती और घरेलू बाजार की केवल घोषणा अलग हैं। भारत को मापन, रिपोर्टिंग, स्वतंत्र सत्यापन, साफ ऊर्जा और पुनर्चक्रण की क्षमता बढ़ानी चाहिए। तकनीकी संवाद को पूर्ण मान्यता या सामान्य छूट तथा प्रस्तावित विस्तार को अंतिम कानून न मानें।

निष्कर्ष में: पारदर्शिता, समान व्यवहार और विकासशील देशों की क्षमता पर नियम-आधारित संवाद जारी रहे। संभावित विदेशी दबाव से निश्चित राहत की आशा में तैयारी न रोकें; विश्वसनीय आँकड़े और कम उत्सर्जन वाला उत्पादन अधिक टिकाऊ प्रतिस्पर्धा देंगे।

स्रोत

- अमेरिकी आधिकारिक सूचना: CBAM पर टिप्पणियों का आमंत्रण, 8 अक्टूबर 2026
- यूरोपीय आयोग: CBAM की लागू व्यवस्था और दायित्व
- भारत सरकार: कार्बन बाजार और CBAM पर तकनीकी संवाद, 12 अक्टूबर 2026

याद रखें: कार्बन आँकड़ों की विश्वसनीयता और स्वच्छ उत्पादन की क्षमता, संभावित व्यापारिक राहत से अधिक टिकाऊ तैयारी हैं।